विकसित देश उठाएं जिम्मेदारी

ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन पर सम्मेलन में बोले प्रधानमंत्री

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने विकसित देशों की ओर इशारा करते हुए कहा कि जो देश ज्यादा ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कर रहे हैं, उन्हें इसे घटाने के लिए भी ज्यादा जिम्मेदारी उठानी चाहिए। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन के खतरों के मद्देनजर 12वीं पंचवर्षीय योजना में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन घटाने का विषय खासतौर पर जुड़ेगा। इसमें ऊर्जा दक्षता और अक्षय ऊर्जा के इस्तेमाल पर विशेष जोर रहेगा।

बृहस्पतिवार को दिल्ली सतत विकास शिखर सम्मेलन-2011' का शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक स्तर पर ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भारत का योगदान मात्र चार है। अगर भारत इसे पूरा बंद कर भी देता है तो भी वैश्विक स्तर पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। विकासशील देश इस मामले में ज्यादा दोषी नहीं हैं और सतत विकास के लिए उनकी मदद की जानी चाहिए।भारत के संदर्भ में प्रधानमंत्री ने जलवायु परिवर्तन के खतरों से निपटने के मौजूदा मानकों को नाकाफी बताया। उन्होंने कहा कि अवशिष्ट प्रदूषण से निपटने के लिए ऐसा प्रावधान होना चाहिए कि प्रदूषण फैलाने वाले भुगतान करें।

पीएम को सतत विकास लीडरशिप अवार्ड

नई दिल्ली (ब्यूरो)। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 'सतत विकास लीडरशिप पुरस्कार' से नवाजे गए। टेरी के इस पुरस्कार को अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हामिद करजई, डोमिनिक के राष्ट्रपति डॉ. लियोनेल फर्नांडीज और सेशेल्स के राष्ट्रपति जेम्स एलिक्स माइकल ने साझा तौर पर प्रदान किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने विकासशील देशों से भी उत्सर्जन कटौती संबंधी बाध्यकारी शर्तें स्वीकार करने की जयराम रमेश की अपील से उलट कहा कि इन देशों को उत्सर्जन कटौती के कानूनी रूप से बाध्यकारी लक्ष्य मानने की जरूरत नहीं है।

Delhi Sustainable Development Summit

DSDS 2011

भारत का अटूट हिस्सा अरुणाचल : मनमोहन

नई दिल्ली (ब्यूरो)। अरुणाचल प्रदेश के खिलाड़ियों को बीजिंग के नत्थी वीजा देने की घटना के बीच प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने बृहस्पतिवार को कहा है कि अरुणाचल भारत का अखंड हिस्सा रहा है और बना रहेगा। उन्होंने दो टूक कह दिया कि किसी नक्शे में पूर्वोत्तर के इस सूबे को चीन का हिस्सा बताने से यह हकीकत बदल नहीं सकती है। प्रधानमंत्री ने यह बयान ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन (एएपीएसयू) के प्रतिनिधिमंडल से बातचीत के दौरान दिया।